संख्याःपी.एल.जी. पीएफ (एफ) 3-7/2021-22 (एसपीबी /एटीआर)
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव,
   हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2
2. सभी उप-कुलपति, विश्वविद्यालय,
   हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
   हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला-2 30 मार्च, 2021

विषयः **माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 10 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक की कार्यवाही।**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में राज्य योजना बोर्ड की दिनांक 10 फरवरी, 2021 को आयोजित बैठक की कार्यवाही सलंग्न करने का निर्देश हुआ है। इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग से सम्बन्धित मदों पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करके सूचना योजना विभाग को भेजने की व्यवस्था करें ताकि उसे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की सूचना एवं जानकारी हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

2. राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही योजना विभाग की बैबवसाईट https://planning.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला -2

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला –2 30 मार्च, 2021

राज्य योजना बोर्ड की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित हैः–

1. राज्य योजना बोर्ड के सभी गैर–सरकारी सदस्य।
2. निजी सचिव माननीय .... मन्त्री हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष राज्य योजना बोर्ड हिमाचल प्रदेश शिमला –2
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला –2
7. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त प्रभागाध्यक्ष, योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि वे अपने प्रभाग से सम्बन्धित मदों पर वांछित कार्यवाही करें।

सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला–2

हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड की 10 फरवरी, 2021 को मान्नीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार (आर्मसडेल भवन) में आयोजित बैठक की कार्यवाही।

(बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।)

1. राज्य योजना बोर्ड, हिमाचल प्रदेश की बैठक दिनांक 10 फरवरी, 2021 को प्रातः 11बजे, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सभागार में माननीय मुख्यमन्त्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वर्ष 2021–22 के लिए प्रस्तावित वार्षिक विकास बजट को अनुमोदित करवाने हेतु आयोजित की गई।

2. सर्वप्रथम सलाहकार (योजना) ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों और स्पेशल अतिथि (Special Invitees) के रूप में ऑनलाईन उपस्थित विभागाध्यक्षों तथा ज़िलों के उपायुक्तों का स्वागत किया व बैठक के आयोजन व कार्यसूची के बारे में अवगत करवाया।

3. इसके पश्चात माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड श्री रमेश चन्द ध्वाला ने माननीय मुख्यमन्त्री, राज्य योजना बोर्ड के सदस्यों, प्रशासनिक सचिवों तथा अन्य अधिकारियों का बैठक में स्वागत किया।

4. अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) द्वारा वार्षिक विकास बजट 2021–22 के मुख्य बिन्दुओं पर प्रस्तुति (Power Point Presentation) दी गई जिसमें प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति से सदन को अवगत करवाया गया। उन्होंने सदन को कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों व उनके प्रति प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, प्रदेश की वित्तीय स्थिति, सकल घरेलु उत्पाद (GDP) की V-Shaped Recovery, योजना व गैर योजना बजट का विलय जैसे घटकों पर विस्तार से जानकारी दी गई।

5. प्रो0 एच0के0 चौधरी, उप–कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर ने Enterpreneurship विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए पूरे प्रदेश में Smart Seed Village Concept को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवता के बीज उपलब्ध हो सकें। एफ. पी. ओ. (Farmers Produce Organisation) के माध्यम से Micro Business Module को अपनाकर उत्तम गुणवता के बीज उपलब्ध करवाने का भी सुझाव दिया ताकि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकें तथा किसानों की उत्पादकता एवं आमदनी बढ़ सके। लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए प्रदेश के स्वर्ण जयन्ती वर्ष के शुभ अवसर पर एक नई "स्वर्णिम जयन्ती लघु कृषक स्वावलम्बी एकीकृत योजना" या "स्वर्ण जयन्ती लक्ष्य" मॉडल के तहत् लम्बवत (Vertical) और समानांतर (Horizontal) खेती किए जाने का भी सुझाव दिया। जिसमें लम्बवत (Vertical) खेती के लिए बांस, लोहे या ईंटों से ढांचा (structure) तथा समानांतर (Horizontal) खेती के लिए बिना ढांचे (structure) के खेती किए जाना प्रस्तावित है ताकि प्रदेश के किसान स्वावलम्बी बन सकें। जैव संसाधनों

व पारम्परिक उत्पादकों के संरक्षण, पंजीकरण व जी.आई टैगिंग करवाने जिसमें मुख्यतः लाल चावल का उदाहरण देते हुए इन उत्पादनों से अच्छी आमदनी होने की आशा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त स्थानीय उत्पादों को Protection of Plant Varities and Farmers Right Authority के माध्यम से संरक्षित किए जाने तथा इन उत्पादों को विश्व स्तर की पहचान दिलवाने हेतु प्रयत्न किए जाने की बात भी कही। कृषि विश्वविद्यालय को Research and Extension Grant उपलब्ध करवाए जाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए योजना तैयार की जा सके। नई शिक्षा नीति के अनुसार Multi Disciplinary Approach अपनाकर प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न विषय पढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया। कृषि, बागवानी व पशुविज्ञान क्षेत्र में अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करके स्वरोजगार की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। अन्त में कलस्टर विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रदेश भर में अम्बरेला विश्वविद्यालय खोलकर उनके आसपास के सभी महाविद्यालयों को अम्बरेला विश्वविद्यालय के अर्न्तगत लाने का भी सुझाव दिया।

6. श्री परविन्द्र कौशल, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं बागवानी विश्वविधालय, नौणी ने इस कोरोना काल में कृषि क्षेत्र एवं वैज्ञानिक समुदाय द्वारा दिए अतुलनीय सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश में कृषि, वानिकी तथा बागवानी के क्षेत्र में उपलब्ध वैज्ञानिक मानव शक्ति (Man Power) के उपयुक्त उपयोग में नं लाए जाने की बात कहते हुए अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र को मिलने वाले कम बजट पर चिंता व्यक्त की।

7. श्री एस0पी0 बंसल, उप-कुलपति, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविधालय, हमीरपुर ने अपने अनुभव के आधार पर देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु दो प्रमुख सुझावों का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने सबसे पहले देश के गांवों की तरफ पुनः रूख करके उन्हें विनिर्माण केन्द्र (Manufacturing hub) बनाना तथा Vitality & Vibrancy of Education Sector पर पुनः ध्यान केन्द्रित करके सतत् विकास लक्ष्य 2, 3 तथा 4 को प्राप्त करके देश को पुनः विश्व गुरू बनाया जा सके। प्रदेश के विकास की बात करते हुए उन्होंने प्रदेश को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का सुझाव दिया जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश की USP (Unique Selling Proposition) तैयार करने की बात कही। मण्डी जिले में बनने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions) Tourism पर बल देते हुए आधारभूत संरचना पर विशेष ध्यान देने तथा प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का सुझाव दिया। प्रदेश में व्याप्त Health & Medical Tourism की अपार सम्भावनाओं की बात करते हुए तथा आयुर्वेदा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लौटाने पर जोर दिया। स्वर्णिम जयन्ती के उपलक्ष्य पर प्रदेश में Snow Carniwal की तर्ज पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाने तथा उसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के आमन्त्रित किए जाने का सुझाव भी दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नई

शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Computing तथा Skill & Vocational जैसे घटकों को अपनाते हुए तकनीकी विश्वविद्यालय को एक नोडल विभाग के तौर पर कार्य करने का सुझाव दिया।

8. श्री संजय कुन्डू, महानिदेशक, पुलिस हि०प्र० ने पूंजीगत निवेश हिमाचल से बाहर होने के कारण GST में होने वाले राजस्व के नुकसान पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा H.P. Land Tenancy & Land Reform Act की धारा 118 में सुधार तथा Land Acquisition प्रक्रिया को भी सरल करने का सुझाव दिया।
9. प्रो० सी० एल० चन्दन, उप-कुलपति, क्लस्टर विश्वविघालय, मण्डी ने वर्ष 2019 में हिमाचल में आयोजित हुई ग्लोबल इनवेस्टर मीट (Global Investor Meet) में साईन हुए 96000 करोड़ रूपये के MOU (Memorandum of Understanding) की बात करते हुए अधिक से अधिक निवेश समझौतों को धरातल पर उतारने हेतु प्रयत्न करने की बात कही जिसमें उन्होंने Ease of Doing Business Index में हुए सुधार की प्रशंसा तो की ही अपितु Land Acquisition में धारा 118 के कारण आने वाली कठिनाईयों से भी सदन को अवगत करवाया। उन्होंने आंध्रप्रदेश के Land Bank Model की तर्ज पर प्रदेश में भी Land Bank तैयार कर निवेशकों को आकर्षित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने सरकार से ऐसी व्यवस्था करने, जिससे प्रदेश में स्थापित उद्योगों में कार्यरत कामगार प्रदेश के भीतर ही रह सके, का भी सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश को ग्लोबल पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने तथा घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करके प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने की भी बात कही।
10. श्री राजकुमार वर्मा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने सर्वप्रथम इस कोरोना काल के दौरान प्रदेश के घट रहे राजस्व पर अपनी चिंता व्यक्त की तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बल देने हेतु हाईड्रो ऊर्जा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया।
11. श्री मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह ने सरकार द्वारा विकास के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले निवेश की बात करते हुए प्रदेश में Income Generating Activities पर विशेष प्राथमिकता देने का सुझाव दिया इसमें उन्होंने बागवानी क्षेत्र में Research & Development तथा Individual Income बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके अतिरिक्त उन्होंने Income Generating Infrastructure तैयार करने का भी सुझाव दिया जिसमें Sports Infrastructure का उदाहरण देते हुए Multi Disciplinary Approach के साथ काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों के उपयुक्त भंडारण, संचालन एवं कियान्वयन हेतु उपयुक्त व्यवस्था करने तथा मांग के अनुसार Warehouse, Godowns & Logistic Facilities तैयार करने का सुझाव दिया ताकि उद्योगपति व ई-कॉमर्स की कम्पनियां एक ही स्थान से स्थानीय उत्पादों को बड़ी संख्या में प्राप्त कर सकें। अंत

में उन्होंने Ease of Doing Business को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में एक Investor Promotion Agency तैयार करने का सुझाव दिया।

12. श्री जे0सी0 शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश में आबकारी (Excise) कर व GST Collection में सुधार की अच्छी सम्भावनाओं की बात कही जिसमें उन्होंने Excise Collection Rules को Enforce करने तथा Collection की Leakages को दूर करने का सुझाव दिया है। उन्होंने प्रदेश की Industiral Investment Policy में उपयुक्त सुधार करने का सुझाव दिया ताकि प्रदेश के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी/कामगार प्रदेश में ही रह सके तथा प्रदेश को Consumption based Tax का राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने प्रदेश में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही जिनके उत्पादों की अधिक से अधिक खपत प्रदेश में होती है ताकि प्रदेश को Consumption based Tax का राजस्व प्राप्त हो सके। उन्होंने Research & Development के माध्यम से प्रदेश में फलों व सब्जियों की पैदावार बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र को बल देने हेतु विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक Rain Water Harvesting Structures तैयार करने का भी सुझाव दिया।

13. श्री रमेश चन्द ध्वाला, माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड ने सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में बड़े स्तर पर खैर के पेड़ों की चोरी हो रही है जिससे सरकार को करोड़ों रूपयों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि वन विभाग के माध्यम से ऐसे सूखे पेड़ों की निलामी की जानी चाहिए ताकि प्रदेश की आमदनी बढ़े। उन्होंने प्रदेश के अधिक से अधिक विकास कार्यों को "विकास में जन सहयोग" योजना के अन्तर्गत करवाने का सुझाव दिया ताकि आम जनता की भागीदारी से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य के अधिकारियों को अधिक से अधिक गाँवों में जाकर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

14. श्री अनिल किमटा, माननीय गैर-सरकारी सदस्य ने "आपदा में अवसर" विषय पर बात करते हुए कोरोना काल के दौरान बाहरी राज्यों से वापिस लौटे पढ़े-लिखे व कुशल प्रदेशवासियों को उनकी कुशलता के अनुसार प्रशिक्षण देने तथा स्वरोजगार की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने लाल चावल की तर्ज पर स्थानीय फसलों काउणी, चीना और कोदरा इत्यादि की पैदावार बढ़ाने तथा इन्हें ख्याति दिलाने व Snow Tourism की तर्ज पर अनछुए पर्यटन के क्षेत्रों को तलाशने का भी सुझाव दिया।

15. श्री सुखराम चौधरी, माननीय ऊर्जा मन्त्री ने निवेशकों को Himachal Pradesh Land Tenancy and Land Reform Act, 1972 की धारा 118 के अन्तर्गत मिलने वाली अनिवार्य अनुमतियों को समयबद्ध करने तथा इन निवेशकों को एक निर्धारित समय सीमा में ही बिजली व पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रेदश में आने

वाले निवेशकों को रहने के लिए मकान बनाने हेतु भी ज़मीन उपलब्ध करवाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने प्रदेश के गैर कृषक हिमाचलियों को धारा 118 के तहत् आने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसी व्यवस्था तैयार करने का सुझाव दिया है जिससे निवेशकों को जिला स्तर पर ही अनुमति मिल सके। अंत में उन्होंने नीलाम हुए खनन के पट्टों की स्वीकृति में होने वाली देरी पर भी चिंता व्यक्त की।

16. श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय शहरी विकास मंत्री ने राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर एक उपयुक्त नाम देने का सुझाव दिया है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश :–

- सर्वप्रथम उन्होंने बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर उनका धन्यवाद किया तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) को उनकी अतिप्रभावी प्रस्तुति देने पर बधाई दी।
- कोविड महामारी के देश में फैलने तथा इस बिमारी के भयंकर प्रकोप से प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं विकास कार्यों पर पडे प्रतिकूल प्रभाव को लगे भारी झटके पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कोरोना महामारी की वैक्सीन तैयार होने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आए कुछ सुधारों के दृष्टिगत देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद व्यक्त की है।
- प्रदेश में निजी निवेश (Private Investment) को आकर्षित करने, राज्य की आमदनी बढ़ाने के स्त्रोतों का विकास करने तथा पर्यटन क्षेत्र को विशेष बल देकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने प्रदेश में विश्व निवेशक सम्मेलन (Global Investor Meet) में निवेशकों द्वारा 96000 करोड़ रुपये के MOU (Memorandum of Understanding) पर सहमति होने और माननीय प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा इसकी सराहना पर सन्तोष व्यक्त किया।
- कोविड महामारी काल के दौरान विभिन्न विभागों, निगमों, निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, मजदूरों, और आम लोगों को दो वक्त की रोटी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे उठाए कदमों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कोरोना काल के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 7161 करोड़ रुपये की सहयोग राशि प्रदान किए जाने पर माननीय प्रधानमन्त्री जी का हृदय से धन्यवाद किया।
- प्रदेश का Ease of Doing Business Index में देशभर में 16वें स्थान से 7वें स्थान को अर्जित करने पर प्रदेश वासियों व अधिकारियों को बधाई दी है।
- वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक विकास बजट के तहत् 9405.41करोड़ रुपये प्रदान करने की बात कही। उन्होंने नई व्यवस्था के तहत चारों उप–योजनाओं अर्थात् सामान्य योजना, अनुसूचित जाति

उप–योजना, जनजातीय उप–योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना का पुनः नामकरण क्रमशः सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम करने तथा इन विकास कार्यकमों में उपयुक्त बजट प्रावधान करने का भी आश्वासन दिया।

- अन्त में, प्रदेश में आमदनी के स्त्रोतों को बढ़ाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने, कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लौटाने हेतु सुझावों का स्वागत किया है। उन्होंने प्रदेश में वित्तीय प्रतिबन्धन को बनाए रखने पर सरकार की कटिबद्धता की सराहना की।

....

परिशिष्ट "क"

List of Participants

Sr. No.	Name	Designation
1.	Sh. Suresh Bhardwaj	Hon'ble UD/ TCP Minister
2.	Smt. Sarveen Chaudhary	Hon'ble S.J&E Minister
3.	Sh. Ram Lal Markanda	Hon'ble Technical Edu. / T.D. Minister
4.	Sh.Virender Kanwar	Hon'ble R.D./P.R. Minister
5.	Sh Bikram Singh	Hon'ble Industries/L.E.P./ Transport Minister
6.	Sh. Sukh Ram Chaudhary	Hon'ble MPP & Power Minister
7.	Sh .Ram Subhag Singh	A.C.S.(Forest/MPP&Power)
8.	Smt.Nisha Singh	A.C.S.(Agriculture/Animal Husbandry)
9.	Sh .Sanjay Gupta.	A.C.S.(SJ&E)
10.	Sh. Manoj Kumar	A.C.S.(Home/FCS&CA)
11.	Sh. R.D.Dhiman	A.C.S (Revenue/Forest)
12.	Sh. Prabodh Saxena	A.C.S.(Finance& Planning)
13.	Sh. Jagdish Chander Sharma	A.C.S.(PWD/Excise& Taxation)
14.	Sh.Kamlesh Kumar Pant	Pr. Secretary(Transport/Sci& Technology)
15.	Sh. Onkar Chand Sharma	Pr. Secretary (Tribal Development)
16.	Sh. Rajneesh	Pr. Secretary (IT/TCP&UD)
17.	Sh.Devesh Kumar	Secretary (GAD)
18.	Sh. Sandeep Bhagnagar	Secretary(RD/PR)
19.	Dr. Ajay Kumar Sharma	Secretary (AYUSH)
20.	Sh. Akshay Sood	Secretary (Cooperation & Housing)
21.	Sh.Vikas Labroo	Secretary (Jal Shakti)
22.	Sh.Rajeev Sharma	Secretary (Education)
23.	Sh. Amitabh Avasthi	Secretary (Health/ Horticulture)
24.	Sh. S.S. Guleria	Secretary (YSS)
25.	Sh C.P. Verma	Special Secretary (TD/Industries)
26.	Prof.Parvinder Kaushal	V.C. Horticulture & Forestry University Nauni, Distt. Solan.
27.	Prof. H.K.Chaudhary	V.C. Agriculture University, Palampur
28.	Prof. S.P. Bansal	V.C. HP Technical University, Hamirpur
29.	B.L. Shukla Finace Officer	Finance Officer ,H.P. University
30.	Prof. Subrata Ghosh	IIT Mandi
31.	Prof. C.L.Chandan	V.C. Sardar Patel Cluster University, Mandi
32.	Sh.Kailash Chand	Deputy Director (TD)
33.	Sh. B.K. Sharma	E-N-C PWD
34.	Sh.DalipNegi Addl.CEO	Addl.C.E.O.

35.	Sh. Naveen Puri	Engineer –in Chief Jal Shakti
36.	Brig.Khushal Thakur	Chairman (SWB) Hamirpur
37.	Sh. Sanjay Kundu	Director General of Police
38.	Sh. D.N. Yadav	IG, Police
39.	Sh. Hamir Chand	Asstt. Director Fisheries
40.	Sh. Sandeep Kumar	MD HRTC
41.	Smt. Reetu Shethi	Non- Official Member
42.	Sh. Raj Kumar Verma	Non- Official Member
43.	Sh. Narender Thakur	Hon'ble MLA Hamirpur
44.	Sh. Sanjay Sharma	Non -Official Member
45.	Sh.You Raj Bodh	Non -Official Member
46.	Sh. Anil Kimta	Non-Official Member
47.	Dr.B.R.Premi	Representative from NABARD
48.	Sh. R.K.Aggarwal	Representative from NABARD
49.	Dr. Basu Sood	Adviser (Planning)
50.	Sh. Surinder Paul	Joint Director (Planning)
51.	Sh. Ravinder Kumar	Dy. Director(Planning)
52.	Sh.Ravi Chand Negi	Dy. Director(Planning)
53.	Sh.Anuj Kumar	Dy. Director(Planning)
54.	Sh. Suresh Kumar	Dy. Director(Planning)
55.	Sh Sanjeev Sood	Research officer(Planning)
56.	Sh Desh Raj	Research officer(Planning)
57.	Smt. Suman Negi	Research officer(Planning)
58.	Sh. Vickrant Joshi	Research officer(Planning)
59.	Sh. Jeevan Kumar	Research officer(Planning)
60.	Smt. Banita Thakur	Assistant Research officer(Planning)
61.	Sh. Dinesh Kumar Sharma	Programmer(Planning)
62.	Sh. Rakesh Gautam	SA(Planning)
63.	Sh. Inder Dutt	Computer(Planning)
64.	Sh. Pankaj Chauhan	JOA (Planning)